(Value in Rs. Crores)

Countries	1989-90		1990-91		1991-92	
	Export	Import	Export	Import	Export	Import
Nepal	83.32	0.56	86.62	81.49	96.55	70.11
Bhutan	—	—	3.91	1.45	2.96	1.16
Bangladesh	458.04	24.30	547.44	31.29	809.44	14.16
Sri Lanka	97.38	23.40	234.90	36.72	429.08	28.06
Pakistan	51.39	53.79	73.60	84.49	98.61	149.98
TOTAL	690.13	102.05	946.47	235.44	1536.64	263.47

(b) There are no formal arrangement for conducting border trade between India and any of these countries. However, all possible steps are taken to promote bilateral trade between India and these countries though exchange of delegations at official/ business levels, participation in trade fairs and operating bilateral trade Agreement/Treaties, except in the case of Pakistan, to facilitate smooth flow of goods between India and these countries. It is as a result of trade *promotion measures that bilateral trade* with these countries has been on the increase during the last three years.

(c) The exchange rate of rupee with the currencies of these countries as on the last day of the years 1990, 1991 and 1992 are as under:

(Indian Rs. 100 equal to)

Effective Date	Bangladesh (Taka) (*)	Pakistan (Pakistani Rupee) (*)	Sri Lanka (Sri Lankan) Rupee) (*)	Nepal (Nepalese Rupee) (**)	Bhutan (Ngultrum) (**)
31.12.90	198.03	121.3650	222.65	167.79	100
31.12.91	148.3325	95.2825	163.52	163.827	100
31.12.92	148.855	98.3375	176.145	164.88	100

(*) These are Asian Clearing Union (ACU) countries. The rate quoted is middle of the buying and selling rates of RBI. (**) RBI are not quoting any rates. However, the rates arrived at by RBI through the rates of these currencies against the dollar are furnished above.

Request for Appointment of a JPC on Dunkel Draft

719. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem appearing in the Statesman dated 5th January, 1993 that the former Supreme Court judge and other prominent personalities had requested Government to consider the appointment of a JPC to inquire into the Dunkel Draft to prepare a report and submit it to Parliament; and

(b) if so, what are the details thereof and what is the reaction of Government in regard thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) It has been stated that the Dunkel Draft raised matters of profound importance to the Indian economy and required to be studied not only by a debate in Parliament but by the process of a JPC.

Government will finalise its views after the conclusions of consultations with political parties. Discussion has already taken place in Lok Sabha on 23.12.92 and the matter is yet to be discussed in Rajya Sabha.

कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में व्यापार मेला परिसर स्थापित किया जाना

720. **श्री अजीत जोगी:**
चौधरी हरि सिंह

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में व्यापार मेला परिसर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त भार (श्री कपालुहीन अहमद): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित अनेक राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के साथ अपनी-अपनी राजधानियों में व्यापार मेले परिसरों की स्थापना करने के संबंध में परस्पर बातचीत कर रही हैं।

भारतीय कृषि क्षेत्र पर डुंकेल प्रस्तावों का प्रभाव

721. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डुंकेल प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद इसका भारतीय कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या यह भी सच है कि डुंकेल प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 1986 को आधार वर्ष माना जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1986 के कृषि उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1986 में देश में व्याप्त भारी अभाव की स्थिति के कारण भारत ने रिकार्ड मात्रा में कृषि उत्पादों का आयात किया था?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (च) सरकार द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत को अल्पावधि और मध्यम अवधि में अपनी घरेलू कृषि नीतियों में किसी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्यात प्रतियोगिता के क्षेत्र में डंकल पाठ में इस समय प्रवृत्त निर्यात प्रोत्साहनों को रोकने का प्रावधान नहीं है। जहां तक बाजार प्रवेश का संबंध है, जब तक भारत में भुगतान-संतुलन की समस्या है, तब तक आयात के लिए मौजूदा और न्यूनतम स्तर पर प्रवेश की अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं है।

प्रमुख कृषि उत्पादकों द्वारा प्रतियोगी आर्थिक सहायता में कटौती के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी जिससे कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए अवसर बढ़ेंगे। भुगतान संतुलन की समस्या के बने रहने तक आयात के मामले में आयात की मात्रा पर अंकुश लगाना संभव रहेगा।

डुंकेल पाठ में गणना के लिए आधार अवधि वर्ष 1986 से 1988 का औसत है।

1986 के वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि वस्तुओं के आयात की सारणी विवरण-1 पर प्रस्तुत है। (नीचे देखिए) इस अवधि के दौरान वर्ष 1988-89 में सर्वाधिक आयात रहा।

वर्ष 1986 के दौरान चुनिन्दा प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन-आंकड़े संलग्न विवरण-2 में दिए गए है।

विवरण-1

भारत द्वारा प्रमुख कृषि वस्तुओं का आयात

(करोड़ रुपए में)

वस्तु	1986-87	1987-88	1988-89
गेहूं	37.27	8.99	433.08
चावल	0.99	2.15	230.64
चीनी	205.24	193.07	0.13